

तालाब पानी से लबालब लेकिन गले सूखे

बीड़ शहर में पीने के पानी का गंभीर संकट

बीड़: (संवाददाता) माजलगांव बैकवॉटर और बिंदूरा जलाशयों में पर्याप्त जल भंडार उपलब्ध होने के बावजूद बीड़ नगर परिषद (इचउ) शहर के नागरिकों को नियमित रूप से पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफल रही है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को १५-१५ दिन या उससे भी अधिक समय बाद पानी मिल रहा है, जिससे पूरे शहर में नाराजगी और हताशा फैल गई है।

माजलगांव बैकवॉटर प्रोजेक्ट, जिसे २००४ में पूरा किया गया था, २०३० तक शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बीते वर्षों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने इस योजना की क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में बीएमसी जल आपूर्ति को नियमित बनाए रखने में संघर्ष



कर रही है और दो मुख्य कारणों से संकट और भी बढ़ गया है:

१. बिजली का बकाया: माजलगांव जल केंद्र की विद्युत आपूर्ति का बड़ा बकाया बीएमसी पर है, जिसके कारण महावितरण बार-बार बिजली काटता है और इससे जल

आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होती है।

२. पाइपलाइन की दिक्कतें: माजलगांव से बीड़ तक की पाइपलाइन में बार-बार तकनीकी खराबियाँ और लीकेज आ रहे हैं, जिससे जल प्रवाह अवरुद्ध होता है।

इसके अलावा जल बिल वसूली की स्थिति भी बेहद खराब है। कई नल धारकों ने अपने बकाया भुगतान नहीं किए हैं, जिससे लाखों रुपये की देनदारी बनी हुई है और जल व्यवस्था पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। जनता का आक्रोश नगर परिषद की मुख्य अधिकारी नीता अंधारे को लेकर भी है, जो पिछले चार वर्षों से पद पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बीएमसी प्रशासन पर नियंत्रण रखने और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।

नागरिक अब स्थायी और पारदर्शी जल आपूर्ति प्रणाली की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें समय पर और विश्वसनीय तरीके से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।

हिंदू-मुस्लिम ओबीसी, भटके-विमुक्त संघर्ष समिति का गठन

डॉ. लक्ष्मण जाधव बीड़ जिल्हाध्यक्ष और खुर्शीद आलम बने शहराध्यक्ष



बीड़, प्रतिनिधि (३ मई २०२५):

आज शनिवार को बीड़ के शासकीय विश्रामगृह में हिंदू-मुस्लिम समाज के ओबीसी, भटके-विमुक्त जाति समुदायों के प्रमुख पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा देश में सभी धर्मों की जातिगत जनगणना करने के फैसले का स्वागत करते हुए उसे ऐतिहासिक बताया गया।

बैठक में लंबे समय से लंबित प्रमुख मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई। इसमें ओबीसी व भटके-विमुक्त समाज के लिए पदोन्नति में आरक्षण, क्रीमी लेयर की शर्त हटाने, प्रत्येक जाति के लिए आर्थिक महामंडल की स्थापना, संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत आयुओं व समितियों की शिफारिशों को लागू करने, सामाजिक-शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, हर जिले में छात्रावास निर्माण, जाति प्रमाणपत्र व जाति वैधता प्रमाणपत्र

की जटिल प्रक्रियाओं को सरल करने जैसी मांगें प्रमुख रहीं।

बैठक में सर्वसम्मति से हिंदू-मुस्लिम ओबीसी, भटके-विमुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की गई और डॉ. लक्ष्मण जाधव को बीड़ जिल्हाध्यक्ष तथा खुर्शीद आलम को शहराध्यक्ष के रूप में निर्वाचन चुना गया। इसके अलावा, अन्य पदों पर निम्नलिखित नियुक्तियाँ की गईं:

जिल्हा उपाध्यक्ष: मनोज चव्हाण

कार्याध्यक्ष: सय्यद फारुख मनियार

सह सचिव: विजय गायकवाड

उपाध्यक्ष: रफिक कुरेशी, शफिक तांबोळी

संघटक: शेख जाकेर

सह संघटक: अशोक दुधाड

कोषाध्यक्ष: वसंतजी अलकुंटे

मार्गदर्शक: सुभाषजी राजूत, प्रकाशजी कानगावकर, हाजी गुलाम जहांगीर

इस अवसर पर मातंग समाज

के नेता अनिलजी चांदणे, ओबीसी नेता प्रकाशजी कानगावकर, सत्री चांदणे, हाशम बागवान, डॉ. संतोष अडागळे, कैकाडी समाज के युवा नेता विजयजी गायकवाड, अक्साद मंसुरी, वडार समाज के नेता वसंतजी अलकुंटे, मसणजोगी समाज अध्यक्ष हनुमंत मोरे, मांग गारुडी समाज के प्रभाकर हतागळे सहित अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में माळी, साळी, छप्परबंद, टकारी, वडार, मनियार, लोहार, मोमीन, कुरेशी, मातीवडार, तांबोळी, शहा, कैकाडी, भावसार, खाटीक, मुस्लिम भंगी, ओतारी, रामोशी, बागवान, मुल्ला-मुलानी, मांग गारुडी, मसणजोगी, फकीर, अत्तार आदि समाजों के प्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति रही।

यह बैठक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक न्याय के संघर्ष को एक संगठित स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नागपुर: साइबर धोखाधड़ी के कारण १० मई से पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट बंद

३ मई २०२५) विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन ने फैसला लिया है कि नागपुर जिले के



सभी पेट्रोल पंपों पर १० मई से किसी भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस निर्णय का कारण हाल ही में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाएँ हैं,

जिनमें कई पेट्रोल पंप मालिकों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

फर्जी ट्रांजेक्शनों के चलते बैंकों ने लाखों रुपये फ्रीज कर दिए, और गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना वह रकम वापस नहीं मिल रही।

यदि जल्दी समाधान नहीं निकला, तो पूरे महाराष्ट्र में डिजिटल पेमेंट बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

इस निर्णय से ग्राहकों को परेशानी होने की संभावना है, और अब सबकी नजर सरकार की प्रतिक्रिया पर है, जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है।

कम्युनिटी रेडियो से हर वर्ग को मंच देने का कार्य हो रहा है : केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन

— रिपोर्ट : जमीर काज़ी, मुंबई देश के कोने-कोने तक पहुंचने के लिए कम्युनिटी रेडियो एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। इस माध्यम के जरिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी बात रखने का मंच उपलब्ध कराया जाए — यह आह्वान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन ने किया।

मुंबई में चल रहे 'वेव्हज २०२५' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित आठवें राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय



के सचिव संजय जाजू, सहसचिव पृथुल कुमार, भारतीय संचार संस्थान (खखचउ) की कुलपति डॉ. अनुपमा भटनगर समेत अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

इस अवसर पर देश भर के

राज्यमंत्री मुरुगन ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो के कार्यक्रमों में स्थानीय समाज की भावनाएं, वहां की संस्कृति, कला, साहित्य, खानपान आदि का सुंदर प्रतिबिंब देखने को मिलता है। 'वेव्हज २०२५' के संदर्भ में यह सम्मेलन एक नई दिशा देता है। कम्युनिटी रेडियो के जरिए न सिर्फ सूचना और मनोरंजन बल्कि महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संवर्धन और ग्रामीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण काम हो रहा है, यह संतोषजनक है। उन्होंने आगे कहा कि आने

वाले समय में कम्युनिटी रेडियो को तकनीक का अधिकतम उपयोग कर ज्यादा समुदायों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य उद्घाटन सत्र के बाद दिनभर विभिन्न सत्रों में कम्युनिटी रेडियो से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं आयोजित की गईं। इन सत्रों में कम्युनिटी रेडियो के आर्थिक विकास, उनकी सशक्तता और तकनीकी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर संवाद हुआ। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों और कई कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।



एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तमिलनाडु के कन्नूर (उपपी) दौरे पर थे। उन्हें पता चला कि फील्ड मार्शल सैम मानेक शां वहाँ के सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। ये जानकर डॉ. कलाम उनसे मुलाकात के लिए अस्पताल पहुँचे।

अस्पताल में पहुँचते ही उन्होंने मानेक शां से उनकी तबियत पूछी और सादगी से कहा -

क्या आपको कोई परेशानी है? कोई

डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम और फील्ड मार्शल मानेक शां की प्रेरक कहानी

शिकायत है? क्या मैं आपकी किसी प्रकार मदद कर सकता हूँ?

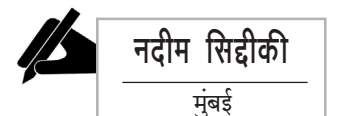
मानेक शां मुस्कुराए और बोले - हाँ सर, मुझे एक शिकायत है।

डॉ. कलाम ने तुरंत पूछा - क्या शिकायत है?

मानेक शां ने विनम्रता से जवाब दिया -

मेरी शिकायत ये है कि मेरे देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति मेरे सामने खड़ा है और मैं बिस्तर पर होने के कारण आपको सलाम नहीं कर पा रहा हूँ।

यह सुनते ही डॉ. कलाम भावुक हो गए। वे आगे बढ़े और मानेक शां का हाथ थाम लिया। दोनों की आँखें भर आईं।



नदीम सिद्दीकी

मुंबई

जब डॉ. कलाम अस्पताल से विदा ले रहे थे, तब मानेक शां ने बताया कि उन्हें फील्ड मार्शल की बढी हुई पेंशन नहीं मिल रही है।

यहाँ बता दें कि साल २००७ में

भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि जीवित फील्ड मार्शल को कार्यरत सेना प्रमुख के बराबर पूरी पेंशन दी जाएगी क्योंकि फील्ड मार्शल को कभी रिटायर्ड नहीं माना जाता।

दिल्ली लौटते ही डॉ. कलाम ने केवल एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही करवाई और लगभग १.३० करोड़ रुपये की बकाया पेंशन की राशि विशेष विमान से वेलिंगटन (ऊटी) भिजवाई।

अब बारी थी मानेक शां के महान चरित्र की।

जब उन्हें वो चेक सौंपा गया, तो उन्होंने पूरी राशि सैनिक राहत कोष में दान कर दी।

एक सैनिक अधिकारी का अपने राष्ट्रपति को सलामी न दे पाने का अफसोस और राष्ट्रपति का उस पर संवेदनशीलता से कार्यवाही करना - ये उदाहरण हैं सम्मान, सेवा और त्याग के।

हमें विचार करना चाहिए कि हम किसे सलामी दें?

इस कहानी से साफ होता है कि भारत के असली हीरो अब बहुत कम बचे हैं - लेकिन जब तक ऐसी प्रेरणाएँ ज़िंदा हैं, उम्मीद बाक़ी है।

यह घटना हमें सिखाती है कि - अपने देश, एक-दूसरे और मानवता के लिए सम्मान और त्याग को ज़िंदा रखना चाहिए।

यही हमें एक सभ्य और संवेदनशील इंसान बनाता है।

तस्वीर नामा प्यासा शहर।

पानी पे पानी से पानी लिखा ।
प्यासे शहर कि कहानी लिखा।
पानी ने भी पलट कर , फिर
अफसर, नेता कि बेईमानी लिखा।



- काज़ी मखदूम

९२७०५७४४४४

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

इन की नापाक नज़र वक्फ की अरबों रुपये की संपत्ति पर है : मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी

बोदवड़ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को-ऑर्डिनेशन कमेटी का शानदार कार्यक्रम

वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अब वक्फ की अरबों रुपये की संपत्ति पर इन चोरों की नापाक नज़र पड़ी है, ये क़ानून बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना और क़ब्ज़ा करना चाहते हैं जो हम किसी भी तरह से होने नहीं देंगे, हम अभी शांतता अमन चैन से सेक्सुलर संविधान के दिये गए रास्ते पर अमल करते हुए आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन अगर ये हिटलर तानाशाह सरकार नहीं मानी तो हम जेल भरो आंदोलन से लेकर जान दो आंदोलन भी करेंगे मगर वक्फ की ज़मीनों को किसी के हलक़ में जाने नहीं देंगे, से ख्यालात का इज़हार सभा के अध्यक्ष हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने बोदवड़ में पेश किए



। इस मौके पर डॉ अब्दुल करीम सालार ने अपने बयान में बताया किस तरह ये सरकार संविधान का उल्लंघन करते हुए वक्फ क़ानून ला रही है और इनके नापाक इरादे क्या है, और कैसे हमको इनका मुक़ाबला

करना है और वक्फ को बचाना है, सुहेल अमीर साहब ने क़ुरान हदीस और हिस्ट्री को सामने रखते हुए उम्मत के जवानों को उभारा और पुर अमन अन्दाज़ में अपने अच्छे अख़लाक से मुक़ाबला करने की नसीहत दी ।

जनाब एजाज़ मलिक साहब ने वक्फ क़ानून की बारीकियां बताते हुए उम्मत को इत्तेहाद और तालीम हासिल करने की बात कही । आखिर में सभा के और इस टीम के भी अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने उम्मत को हौसला बढ़ाते हुए हालात से मायूस ना होने की नसीहत दी और कहा कि बड़े बड़े आए और चले गए ये भी आये हैं और चले जायेंगे,कोई डर और खौफ की बात नहीं बस जोश के साथ होश की ज़रूरत है कोई शैतान फायदा उठाकर राजनीतिक रोटियाँ ना सेख लें, माहौल को खराब होने नहीं देना है ये हिन्दू मुस्लिम का झगडा नहीं है इसलिए हिन्दू मुस्लिम होने मत देना । ये प्रोग्राम बेहद

कामियाब रहा । जलगांव से वक्फ कारवाँ की टीम अब्दुल अजीज़ सालार, शाहिद मेम्बर, कय्यूम शाह सर, इरफान सालार, साबिर मुस्तफाबादी और सभी ज़िम्मेदार बड़ी तादाद में मौजूद थे । सबने इस कामियाब कार्यक्रम पर बादवड़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया । इस कार्यक्रम को कामियाब बनाने में अल्हाज़ सईद बागबान, शेख ज़फर नगरसेवक, मौलाना अमीन इशाती, मौलाना इश्तेयाक,हाफिज़ फिरोज़,शेख अकरम, मोहम्मद अतीक मेकेनिकल और कालू भाई मंडप वाले और सभी जवानों की बड़ी मेहनत रही, मुफ्ती हारून की दुआ पर जलसे खतम हुवा ।

बीड़ बस स्थानक पर मुसाफ़िरों की भारी भीड़, एमएसआरटीसी असमर्थ



बीड़: गर्मी की छुट्टियाँ और शादी-ब्याह का मौसम शुरू होते ही बीड़ बस स्थानक पर यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो गई है। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब यात्री ड्राइवर केबिन और बसों की खिड़कियों तक से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गंभीर हादसों की आशंका बढ़ गई है।

सूत्रों के अनुसार बीड़ एमएसआरटीसी विभाग को बसों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अधिक मांग वाले मार्गों पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू करनी पड़ रही हैं। खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बैठने और यात्रा करने में काफी कठिनाई हो रही है।

इस बीच, नए बस स्थानक का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन वर्तमान की अव्यवस्था ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी है। सुविधाओं की कमी के चलते बस स्टॉप पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा बनाए रखना कठिन हो गया है।

परिस्थितियों को देखते हुए एमएसआरटीसी ने उन मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है जहाँ यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है – विशेष रूप से पीक सीज़न और छुट्टियों के दौरान। यात्रियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए ताकि यात्रा व्यवस्था सुधरे और भीड़ नियंत्रित रहे।

अगर लाडली बहना योजना की सब्सिडी में कटौती बंद नहीं हुई तो होगा जोरदार आंदोलन- पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल का ऐलान

जालना, ३ मई २०२५ (रिपोर्टर: शेख अहमद अकबर जालनवी) राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी लाडली बहना योजना की सब्सिडी में कटौती कर उन बहनों के साथ अन्याय कर रही है जिनके भरोसे वह सत्ता में आई थी। यह गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल ने चेतावनी दी है कि यदि चुनावी वादे के अनुसार हर माह २१०० रुपये की सब्सिडी तुरंत नहीं दी गई, तो लाडली बहनों को साथ लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा।



गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिंदे सेना गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणापत्र में लाडली बहनों को २१०० रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। इस वादे के आधार पर राज्य भर की महिलाओं से आवेदन मांगे गए थे। बिना किसी स्पष्ट पात्रता मानदंड के, और बिना ही कई जांच-पड़ताल के, चुनाव से पहले सही कई महिलाओं के खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। इसका लाभ उठाकर लाखों महिलाओं ने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को भारी संख्या में वोट दिए, जिसके चलते वे सत्ता में आईं।

लेकिन अब पूर्व विधायक कैलाश

गोरंट्याल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सब्सिडी की रकम में सीधे ५०० रुपये की कटौती कर रही है और वादा किए गए २१०० रुपये की बजाय सिर्फ १५०० रुपये ही दे रही है। उन्होंने कहा कि जिन लाडली बहनों के कंधों पर चढ़कर सत्ता हासिल की गई, अब उन्होंने के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। गोरंट्याल ने स्पष्ट कहा कि लाडली बहनों को सिर्फ चुनावों में वोट के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए और घोषणापत्र के अनुसार उन्हें २१०० रुपये के साथ अन्याय की मासिक सब्सिडी तुरंत दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी लाडली बहनों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसानों की कर्जमाफी और मुफ्त बिजली का क्या हुआ? चुनावों में बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आई भाजपा की सहयोगी पार्टियों के नेता अब अपने वादे भूल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार लाडली बहनों के साथ अन्याय कर रही है और किसानों को भी उनके हक से वंचित कर रही है।

गोरंट्याल ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि लाडली बहनों, किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही एक व्यापक जनआंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कनिष्ठ महाविद्यालयों में घड़ी की तासिका पद्धति पर कार्यरत शिक्षकों के मानधन में दोगुनी वृद्धि-प्रा. अमर शेख

मुंबई, राज्य सरकार ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों और कनिष्ठ महाविद्यालयों में घड़ी की तासिका पद्धति (शिी श्रशलीीीश लरीळी) पर कार्यरत शिक्षकों के मानधन में दोगुनी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस आशय का शासन निर्णय ३० अप्रैल को जारी किया गया है। यह जानकारी राष्ट्रावादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) के पदवीधर संघटना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. अमर शेख ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

प्रा. शेख ने बताया कि यदि किसी मान्यताप्राप्त स्कूल या महाविद्यालय में किसी विषय के लिए आवश्यक पूर्णकालिक शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उस विषय के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की तासिका तत्त्व पर नियुक्ति की जाती है और उन्हें प्रति व्याख्यान (घड़ी की तासिका) के आधार पर मानधन दिया जाता है।

पूर्व में यह मानधन माध्यमिक विद्यालयों के लिए १२० रुपये प्रति तासिका था, जिसे अब बढ़ाकर २५० रुपये कर दिया गया है। वहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पहले १५० रुपये प्रति तासिका मिलते थे, जिसे अब ३०० रुपये किया गया है।

इस निर्णय से राज्यभर में घड़ी की तासिका पद्धति पर कार्यरत हजारों शिक्षकों को लाभ होगा। प्रा. अमर शेख ने बताया कि इस मांग को लंबे समय से मराठवाड़ा शिक्षक क्षेत्र के विधायक विक्रम काळे ने निरंतर उठाया था, जिसका यह सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

शिक्षक संघटनाओं में इस निर्णय से संतोष व्यक्त किया गया है और उम्मीद जताई गई है कि सरकार आगे भी ऐसे शिक्षक कल्याणकारी निर्णय लेती रहेगी।

खरीफ सीजन से पहले किसानों को बीज, खाद और फसल ऋण उपलब्ध कराया जाए: पालक मंत्री पंकजा मुंडे

जालना, ३ मई: महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन मंत्री तथा जालना जिले की पालक मंत्री पंकजा मुंडे ने निर्देश दिए हैं कि खरीफ सीजन की बुआई शुरू होने से पहले किसानों को बीज, रासायनिक खाद और फसल ऋण समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को समय रहते समुचित योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

यह बातें उन्होंने जिला नियोजन समिति सभागार में आयोजित खरीफ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक में कहीं। बैठक में सांसद कल्याण काळे, विधायक अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, संतोष दानवे, नारायण कुचे, हिकमत उद्याण, राजेश राठोड सहित जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल, प्रभारी पुलिस अधीक्षक आयुषकुमार नोपाणी, उपजिल्हाधिकारी रीता मैत्रवार, कृषि सहसंचालक पी.आर. देशमुख और कृषि अधीक्षक जी.आर. कापसे प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

पालक मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग को प्रस्तावित बुआई क्षेत्र के अनुसार बीज और खाद का सूक्ष्म नियोजन करना चाहिए ताकि किसानों को समय पर संसाधन मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को पर्याप्त वर्षा के बाद ही बुआई करने की सलाह दी जाए ताकि दोबारा बुआई की नौबत न आए। इसके लिए कृषि विभाग को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। साथ ही बीज चयन, बुआई की विधि, समय और फसल रोगों की रोकथाम पर भी विशेष जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नकली बीज और रासायनिक खाद की बिक्री रोकने के लिए विशेष दल गठित किए जाएं और दोषियों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। शिकायत मिलने पर नमूने जांचने के बजाय गोदामों की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। खाद की जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर भी

सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को धोखा न हो। साथ ही, जून तक किसानों को बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए ताकि उन्हें बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें।

पालक मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना और मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना के लाभ पात्र किसानों को समय पर मिलें, इसके लिए नियोजन किया जाए। गोपीनाथ मुंडे किसान अपघात बीमा योजना

के लाभ भी समय पर पहुंचने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले में पानी की कमी से प्रभावित गांवों को टैंकर, नल योजनाएं और कुओं के अधिग्रहण जैसे उपायों से तुरंत पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष खरीफ सीजन में जालना जिले के ६.२९ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से २.२१ लाख हेक्टेयर पर सोयाबीन और २.९१ लाख हेक्टेयर पर कपास की फसलें लगाई जाएंगी। कपास की बुआई के लिए

११.५१ लाख बीज पैकेट की आवश्यकता होगी जिसका नियोजन किया गया है। सोयाबीन के लिए ६५% बीज किसान स्वयं के पास रखते हैं, जबकि शेष ५७,५६५ क्विंटल बीज की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा ज्वार, मूँग, तूरार, उड़द, भुईमूँग, सूरजमुखी और तिल की बुआई के लिए ७३,०७६ क्विंटल बीज की मांग दर्ज की गई है। कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज और कीटनाशकों का समुचित नियोजन किया गया है, यह जानकारी कृषि अधीक्षक जी.आर. कापसे ने दी। बैठक की शुरुआत में पालक मंत्री पंकजा मुंडे ने कृषि विभाग के व्हाट्सएप चैनल और घड़ीपत्रिका (कृषि कैलेंडर) का लोकार्पण किया। इस बैठक में उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अग्रणी बैंक के मैनेजर प्रेषीत मोघे, जिला सहकारी निबंधक परमेश्वर वरखडे, कृषि विकास अधिकारी प्रभाकर बनसावडे सहित उपविभागीय व तालुका कृषि अधिकारी उपस्थित थे।

पहलगाम हमले के बाद सौहार्द्र का संदेश: हेमांशी नरवाल, मथुरा- वृंदावन के पुजारियों और देश के जिम्मेदार नागरिकों का संदेश

जम्मु-कश्मीर के पहलगाम स्थित बेसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। इस हमले में २६ लोगों की जान चली गई, जिनमें भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। वह अपनी नई नेवेली पत्नी हेमांशी नरवाल के साथ हनीमून पर गए थे। इस हमले के बाद कुछ टीवी चैनलों और उकसावेबाज़ तत्वों ने देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस विपदा की घड़ी में देश में भाईचारे की मिसालें भी सामने आईं, जो नफरत फैलाने वालों के लिए करारा जवाब हैं।

लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हेमांशी नरवाल, जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं, ने अपने पति की शहादत के बाद एक मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा, मैं देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि कृपया इस घटना के आधार पर मुसलमानों या कश्मीरियों को निशाना न बनाएं। हम शांति चाहते हैं, और हाँ, न्याय भी चाहते हैं। लेकिन

नफरत नहीं। विनय ने देश के लिए जो किया, उसे याद रखें।

यह भी सामने आया है कि हमले के दौरान एक कथित वीडियो में हेमांशी कहती सुनी गई – मैं भेलपुरी खा रही थी, मेरे पति मेरे साथ थे। एक व्यक्ति आया और पूछा कि क्या वे मुसलमान हैं। जब उन्होंने इनकार किया तो उसने गोली मार दी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के २७वें जन्मदिवस (२७ अप्रैल) को हरियाणा के करनाल में 'नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स' द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी पत्नी और माँ की आंखों में आंसू थे। इस शिविर के माध्यम से संदेश दिया गया कि आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूमों का खून बहाया, लेकिन हम इस रक्तदान से कई जिंदगियां बचा रहे हैं – यही विनय को सच्ची श्रद्धांजलि है। विनय और हेमांशी की शादी १६ अप्रैल २०२५ को हुई थी और वे हनीमून पर पहलगाम गए थे,

जहां २२ अप्रैल को उन पर आतंकवादी हमला हुआ। इसी बीच नौसेना के पहले प्रमुख एडमिरल रामदास कटारी की बेटी ललिता रामदास ने भी हेमांशी को एक भावुक पत्र लिखकर उनके बयान की सराहना की।

देशभर से सौहार्द्र की आवाज़ें तब और बुलंद हुईं जब उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों और महंतों ने मुसलमानों के



बहिष्कार की मांगों को सिरों से खारिज कर दिया। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के राजभोग सेवा अधिकारी ग्यानेंद्र किशोर गोस्वामी ने कहा,

ब्रजमंडल में भक्ति सर्वोच्च है। यह ज्ञान और वैराग्य से भी ऊपर है। जो भी श्रद्धा लेकर आता है, उसका स्वागत होता है। उन्होंने कहा कि भगवान बिहारी जी कभी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने अकबर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह स्वामी हरिदास जी से मिलने आए थे और इत्र चढ़ाया था, तो वह स्वीकार किया गया था।

गोस्वामी ने यह भी बताया कि मंदिर में भजन गाने वाले, मुकुट और वस्त्र कढ़ाई करने वाले कारीगरों में बड़ी संख्या मुसलमानों की होती है। अगर ठाकुर जी ने रसखान और रहीम को भजन लिखने से नहीं रोका, तो हम कैसे रोक सकते हैं? – ऐसा कहना था गोकुल के डंगहटी मंदिर के पुजारी लाला पंडित का। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण प्रेम के देवता हैं, उनकी धरती पर नफरत की कोई जगह नहीं।

मथुरा के काली मंदिर के महंत दिनेश चतुर्वेदी ने भी कहा, मंदिर सार्वजनिक स्थल हैं, किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर

बहिष्कार करना उचित नहीं है। उन्होंने जोड़ा, कश्मीर में कई मुसलमानों ने पर्यटकों की मदद की है। हम सबको एक ही रंग में नहीं देख सकते।

बलदेव के दाऊजी मंदिर के पुजारी गोविंद पांडे ने कहा कि मंदिर हर उस व्यक्ति का स्वागत करता है जो दर्शन के लिए आता है। स्थानीय मुसलमान बहुत सहयोगी हैं।

मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी राकेश चतुर्वेदी ने भी कहा, जो कोई भी दर्शन के लिए आता है, वह हमारे लिए दर्शनार्थी है। कुछ लोग समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे तत्वों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इन सभी बयानों और घटनाओं से साफ संदेश गया है कि भारत का आम नागरिक अब भी आपसी भाईचारा और गंगा-जमुनी तहजीब को सबसे ऊपर मानता है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद नफरत फैलाने की कोशिशों को इन शांति और सौहार्द्र के संदेशों ने करारा जवाब दिया है।